**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1574**

**1 जनवरी, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**पश्चिमी बंगाल में भारतीय पटसन निगम द्वारा न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर पटसन की खरीद**

**1574. सुश्री दोला सेन:**

 **क्‍या वस्‍त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क): पश्चिमी बंगाल में भारतीय पटसन निगम (जे सी आई) के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर कच्‍चा पटसन खरीदने में असमर्थ रहने के क्‍या कारण हैं; और

(ख): इससे उबरने और इसे ठीक करने हेतु केन्‍द्रीय सरकार की इस संबंध में क्‍या भावी योजनाएं हैं?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** जी, नहीं। भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) नामक इस मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एमएसपी अभियान चला रहा है और 90 खरीद केंद्रों के माध्‍यम से निर्धारित गुणवत्‍ता वाली कच्‍ची पटसन की खरीद कर रहा है जिनमें से 48 विभागीय खरीद केंद्र और 13 सहकारी एजेंसियां पश्चिम बंगाल में हैं। जेसीआई ने अभी तक 354248 क्विंटल कच्‍ची पटसन की खरीद की है जिसमें से 217896 क्विंटल पश्चिम बंगाल से खरीदे गए हैं और इसका खरीद संबंधी अभियान अभी भी जारी है। आवश्‍यकता और मांग के आधार पर जेसीआई द्वारा इसके अतिरिक्‍त खरीद केंद्र खोले जा सकते हैं।

भारत सरकार**,** जहां कहीं और जब कभीबाजार मूल्‍य, एमएसपी से नीचे रहता है तो भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) द्वारा एमएसपी पर पटसन की खरीद सुनिश्‍चित करके भारत में पटसन उत्‍पादकों कोन्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि लागत और मूल्‍य आयोग, उत्‍पादन की लागत, समग्र मांग/आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍य आदि जैसे कारकों को ध्‍यान में रखते हुए प्रत्‍येक पटसन मौसम (जुलाई-जून) के लिए टीडी-5 श्रेणी की कच्‍ची पटसन के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की सिफारिश करता है।

सरकार ने पटसन की एमएसपी 2016-17 में 3200 रुपए प्रति क्‍विंटल से बढ़ाकर 2017-18 में 3500 रुपए प्रति क्‍विंटल की कर दी है जिसमें पिछले वर्ष के मूल्‍य की तुलना में 9.38% की वृद्धि हुई है।

\*\*\*\*